



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 27 जून, 2005/6 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2005

संख्या एच०पी०इ०आर०सी०/सचिव/704/2005-1011.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 91 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने

वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बावत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, पर विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्योथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला -171002 को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2005 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "परामर्शी" में कोई व्यक्ति, फर्म, निकाय या व्यक्तियों का संघ, जो आयोग के रोजगार में नहीं है, जिसे तथा जिसके पास कोई विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या दक्षता हो और जिसे अधिनियम के अनुसार आयोग द्वारा किये जाने वाले किसी कृत्य के सम्बन्ध में आयोग की सहायता के लिए नियुक्त किया जा सके;

(ङ) "अधिकारी" से आयोग का अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसकी अनुपस्थिति में सचिव के कर्तव्यों तथा कृत्यों के निर्वहन के लिये आयोग द्वारा सीमित कालावधि के लिये प्राधिकृत आयोग का अन्य अधिकारी भी है;

(छ) इन विनियमों में होने वाले सभी शब्दों या पदों के, जो इन में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं; उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिया गया होगा।

3. कार्यक्षेत्र.— (1) अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आयोग, स्वविवेकानुसार, किसी भी मामले में, मामले की प्रकृति तथा जटिलता के ध्यान में रखते हुए, ऐसी प्रक्रिया, जिसे वह समुचित समझे, अपना कर अपेक्षित परामर्शियों की नियुक्ति कर सकता है।

(2) परामर्शियों की नियुक्ति सामान्यतः दिन-प्रतिदिन के नेमी कार्य, जिनके लिए स्टाफ उपलब्ध है, के लिए नहीं की जाएगी।

(3) विशिष्ट कार्यों, जिनके लिए या तो आयोग के स्टाफ में योग्यता उपलब्ध नहीं है अथवा जहाँ पर कार्य की प्रकृति तकनीकी, विशिष्ट या समयबद्ध है, के लिए परामर्शियों को नियुक्त किया जाएगा।

(4) प्रत्येक मामले में परामर्श सेवायें प्रदान करने से पूर्व परामर्शी और आयोग के बीच सहमति के अनुसार विस्तृत शर्तें तय की जाएँगी।

(5) विनियोजन की शर्तों में, परामर्शी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्य के सही स्वरूप, प्रत्येक कार्य की पूर्णता के लिए अनुज्ञेय समय तथा प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में परामर्शी द्वारा पूर्ण किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य को उल्लिखित किया जाएगा।

4. परामर्शियों का वर्गीकरण.— (1) वैयक्तिक परामर्शी को सलाहकार, रिटेनर परामर्शी और परामर्शी उनकी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर तीन स्तरों में से किसी एक में वर्गीकृत किया जाएगा :—

श्रेणी 1	न्यूनतम अर्हताएं 2	न्यूनतम अनुभव 3
(क) <u>सलाहकार</u>	डॉक्ट्रेट की उपाधि/ स्नातकोत्तर उपाधि।	डाक्ट्रेट की उपाधि सहित 15 वर्ष। स्नातकोत्तर उपाधि सहित 18 वर्ष।
(ख) <u>रिटेनर परामर्शी</u>	डॉक्ट्रेट की उपाधि/ स्नातकोत्तर उपाधि।	डाक्ट्रेट की उपाधि सहित 15 वर्ष। स्नातकोत्तर उपाधि सहित 18 वर्ष।
(ग) <u>परामर्शी</u> (i) <u>वरिष्ठ परामर्शी</u>	डॉक्ट्रेट की उपाधि/ स्नातकोत्तर उपाधि।	डाक्ट्रेट की उपाधि सहित 8 वर्ष। स्नातकोत्तर उपाधि सहित 12 वर्ष।

1	2	3
(ii) परामर्शी	डॉक्ट्रेट की उपाधि/स्नातक उपाधि।	डॉक्ट्रेट की उपाधि सहित 3 वर्ष। स्नातकोत्तर की उपाधि सहित 5 वर्ष। स्नातक की उपाधि सहित 8 वर्ष।
(iii) कनिष्ठ परामर्शी	स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातक उपाधि।	1 वर्ष

टिप्पणी.— वकीलों, लेखाकारों, इंजीनियरों तथा अन्य अत्यन्त विशेषित व्यवसायियों के मामले में न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं संगत व्यावसायिक अर्हताएं होंगी।

(2) आयोग उपयुक्त मामलों में, लिखित रूप में अभिलेखित कारणों के आधार पर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी व्यक्ति की समग्र विशेषज्ञता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अथवा न्यूनतम अनुभव में छूट देते हुए परामर्शी के रूप में अभि-नियुक्ति के लिए विचार कर सकता है।

5. शुल्क एवं अन्य प्रभार.— (1) जहाँ विनिर्दिष्ट काम के लिए वैयक्तिक परामर्शी नियुक्त करना हो, जहाँ व्यक्ति का अनुभव, विशेषज्ञता, अर्हताएँ और प्रात्यायक सर्वोपरि आवश्यकता हो और अपेक्षित अर्हताएँ तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति विरले ही उपलब्ध हों, तो वैयक्तिक परामर्शी को मासिक आधार पर रखकर दैनिक अथवा मासिक आधार पर सेवाओं के लिए समेकित पारिश्रमिक का, जिसे आयोग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए, भुगतान किया जाएगा।

(2) दैनिक आधार पर सेवाओं के लिए, प्रतिदिन का पारिश्रमिक इस शर्त के अध्वधीन रहते हुए कि दैनिक दर पर बचनबद्धता सामान्यतः एक माह में 7 कार्य दिवसों से अधिक के लिए नहीं होगी, निम्नानुसार होगी:—

वर्ग	प्रतिदिन का पारिश्रमिक	दैनिक भत्ते के लिए प्रतिदिन एकमुश्त राशि (जब प्रवास पर हो)
1	2	3
(क) सलाहकार	5,000/-रुपये	2000/- रुपये
(ख) रिटेनर परामर्शी	आयोग तथा रिटेनर परामर्शी के बीच आपस में निर्धारित समेकित मासिक शुल्क।	जो हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रेड-I अधिकारियों को अनुज्ञप्त है।

1	2	3
(ग) (i) वरिष्ठ परामर्शी	3,000/- रुपये	1500/- रुपये
(ii) परामर्शी	2,000/- रुपये	1500/- रुपये
(iii) कनिष्ठ परामर्शी	1000/- रुपये	1000/- रुपये

(3) संस्थागत परामर्शियों के मामले में सामान्यतः दर प्रतियोगी बोली के माध्यम से यथा अवधारित होगी। अपवादित मामलों में जहाँ एकल स्रोत चयन विनियम 13 में वर्णित कारणों से अपेक्षित हो, वैयक्तिक परामर्शियों के भिन्न-भिन्न स्तरों की दरें प्रस्तावों में परामर्शी समय की आबंटित लागत की औचित्य के अवधारण में प्रयोग की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त परामर्शी समय की लागत के अतिरिक्त अधिकतम 10 प्रतिशत, ऊपरी कार्यालयीन खर्च, जैसे कि दूरभाष, द्विप्रतिलिपिकरण, फैंक्स इत्यादि व्यय, के लिए अनुज्ञेय होंगे। परामर्शी समय की लागत के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा तक आकस्मिक व्यय की राशि जहाँ कहीं अपेक्षित हो आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर देय होगी।

(4) रिटेनर परामर्शी की दशा में, मासिक समेकित ऊपरी कार्यालयीन खर्च, जैसे कि दूरभाष, द्विप्रतिलिपिकरण, फैंक्स इत्यादि के व्यय तथा आकस्मिक व्यय की राशि मासिक समेकित शुल्क के एक तिहाई तक सिमित होगी।

(5) परामर्शियों को, जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न किया जाए, अपने मुख्यालयों पर आयोग के साथ कार्य करना होगा। जहाँ परामर्शी द्वारा कार्यालयीन यात्रा और काम के सामान्य स्थान से दूरस्थ स्थान पर ठहरने पर खर्च उपगत किया जाना हो, तो आयोग अतिरिक्त खर्चों की दैनिक भत्ते के रूप में एक मुश्त राशि में प्रतिपूर्ति करेगा। दिनों की संख्या जिन पर यह एक मुश्त देय होगी प्रत्येक मामला समुचित रूप में अवधारित होगा। यात्रा की लागत, की प्रतिपूर्ति समुचित यात्रा श्रेणी के द्वारा, जैसी कि आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए, पृथक्तः की जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रेड-I के राजपत्रित अधिकारी के लिए अनुज्ञेय से कम नहीं होगी।

(6) देय फीस के संबंध में ये विनियम परामर्शी के रूप में लगे भूतपूर्व तथा सेवा निवृत्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

6. परामर्शियों की नियुक्ति.— (1) विशिष्ट कार्यों के लिए परामर्शियों की नियुक्ति हेतु संदर्भों के निबन्धन (टी.ओ.आर.) आयोग के एक अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा उन्हें आयोग का अनुमोदन लेने के लिए सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) टी.ओ.आर. में वर्णित सेवाओं के कार्य-क्षेत्र उपलब्ध बजट के अनुरूप होगा।

(3) आयोग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव संयुक्त रूप में, या तकनीकी और वित्त प्रस्ताव पृथक-पृथक रूप में, आमंत्रित करने के लिए निर्णय ले सकेगा ।

(4) आयोग तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम अर्हताकारी अंक निर्धारित करेगा ।

(5) आयोग द्वारा संदर्भों के निबन्धन (टी.ओ.आर.) के अनुमोदन के पश्चात्, सचिव इच्छुक परामर्शियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाने वाला अनुरोध-पत्र तैयार करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मामले में समुचित प्रचार किया गया है । तथापि, उन मामलों में लोक विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक नहीं होगा, जिनमें शुल्क मूल्य पाँच लाख रुपये से कम है, आयोग आवेदन या प्रस्ताव या नामांकन ऐसे व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों तथा संस्थाओं से आमंत्रित कर सकेगा, जैसा आयोग उचित समझे । इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

7 प्रस्तावों के अनुरोध.— प्रस्तावों की अपेक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

- (1) आमंत्रण-पत्र जिसमें आयोग का आशय कथित करते हुए परामर्शी सेवाओं के लिए अनुबंध करने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तारीख, समय और पते का उल्लेख हो ।
- (2) परामर्शियों को जानकारी देने में ऐसी सभी आवश्यक जानकारीयां समाविष्ट होंगी जो कि मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उत्तर देने योग्य प्रस्तावों को तैयार करने में परामर्शियों की सहायता करेगा और मूल्यांकन मापदण्डों तथा तथ्यों तथा उनके अपने-अपने भारों तथा न्यूनतम पूर्व अर्हता गणक दर्शाते हुए सहायता करेगा ।
- (3) संदर्भों के निबन्धन (टी.ओ.आर.) उद्देश्यों, लक्ष्यों और समनुदेश के क्षेत्र और ऐसी पृष्ठभूमि की जानकारी देने जिसमें विद्यमान सुसंगत अध्ययनों की सूची और आधारभूत आंकड़े सम्मिलित करते हुए उनके प्रस्तावों को तैयार करने में परामर्शियों की सुविधा के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित करके तैयार किए जाएंगे । यदि ज्ञान, प्रशिक्षण का अंतरण उद्देश्य है, तो टी.ओ.आर. में प्रशिक्षित होने वाले कर्मचारीवृन्दों की संख्या का विवरण देना होगा । टी.ओ.आर. सेवाओं की सूची और समनुदेश कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सर्वे और टी.ओ.आर. के प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित आशयित परिणामों (उदाहरणार्थ रिपोर्ट डाटा: सर्वे, मानांकन आदि) को सूचीबद्ध करेगा ।

(4) संविदा अनुसूचि — “क” में प्रोफार्मा के अनुसार होगा ।

8. प्रस्तावों की प्राप्ति.— (1) परामर्शियों के लिए उनके प्रस्तावों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय अनुज्ञात किया जाएगा, जबकि अनुज्ञात समय समनुदेशन पर निर्भर होगा। यह सामान्यतः दो सप्ताहों से कम का नहीं होगा। इस अवधि के दौरान टी.ओ.आर. में दी गई जानकारी के बारे में फर्म स्पष्टीकरण मांग सकेंगी।

(2) आयोग, प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा में विस्तार करने का विनिश्चय, जैसा कि उसके द्वारा समुचित समझा जाए, कर सकेंगी।

(3) आयोग द्वारा नियुक्त की गई वार्ता समिति के समक्ष के सिवाय समय सीमा के निकल जाने के पश्चात् तकनीकी या वित्तीय प्रस्तावों में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्तावों को सीलबन्द कवर में प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ आयोग यह विहित करता हो कि पृथक तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं वहाँ उन्हें एक पृथक सीलबन्द कवर में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. प्रस्तावों का मूल्यांकन.— प्रस्तावों को गुणवत्ता तथा साथ-साथ ही कीमत दोनों के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। जहाँ आयोग यह विनिश्चय करता हो कि प्रस्तावों को तकनीकी और वित्तीय आधार पर मूल्यांकित किया जाए; वहाँ तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन की पहुंच वित्तीय प्रस्तावों तक तब तक नहीं रहेगी जब तक कि तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण न हो जाए।

10. तकनीकी मूल्यांकन.— (1) आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट समिति द्वारा निम्नलिखित मानदंड को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड 1 से 100 तक के स्केल पर चिह्नित रहेगा और प्रत्येक मानदंड के अंक औसत तकनीकी अंक होने के लिए मापित किए जाएंगे। निम्नलिखित श्रेणियों में माप आयोग की तकनीकी समिति के अनुमोदन से प्रत्येक प्रस्ताव के लिए मापे गए औसत तकनीकी अंक की गणना के लिए उपयोग में लाए जाएंगे।

मानदण्ड	माप की श्रेणी
कर्तव्य भार के लिए परामर्शी का सुसंगत अनुभव	0.10 से 0.20
प्रस्तावित पद्धति की गुणवत्ता	0.20 से 0.50
प्रस्तावित प्रमुख स्टाँफ की अर्हताएं	0.30 से 0.60
आयोग के स्टाँफ को ज्ञान के अंतरण की सीमा	0.00 से 0.05

टिप्पणी.— आयोग द्वारा अनुमोदित माप के मेल का योग एक तक होना चाहिए।

(2) जहां कर्तव्यभार, प्रमुख स्टाँफ के पालन पर निर्भर करता हो वहाँ प्रस्ताव, नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की अर्हताओं पर निम्नलिखित मानदण्ड को उपयोग में लाते हुए मूल्यांकित किया जाएगा:—

(क) सामान्य अर्हताएं.— सामान्य शिक्षा, अनुभव के वर्ष, धारित पद, स्टाँफ के रूप में फर्म के साथ परामर्श का समय अन्य देशों में अनुभव।

(ख) कर्तव्यभार के लिए पर्याप्तता.— शिक्षा, प्रशिक्षण, विशिष्ट सेक्टर में अनुभव, क्षेत्र विषय और विशिष्ट कर्तव्यभार के प्रति सुसंगतता ।

(ग) क्षेत्रीय अनुभव.— प्रशासनिक पद्धति का ज्ञान, स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर संगठन और संस्कृति ।

(3) तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण होने के पश्चात् आयोग उन परामर्शियों को सूचित करेगा जिनके प्रस्तावों को न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं हुए हैं या संदर्भ में निबन्धन के बारे में अप्रतियुत्तरकारी समझे गए और चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उनके वित्तीय प्रस्तावों को बिना खोले वापिस कर दिया जाएगा । इसके साथ-साथ उन परामर्शियों को जिन्होंने अर्हता अंक प्राप्त कर लिए हैं, वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की तारीख और समय देते हुए सूचित किया जाएगा ।

11. वित्तीय मूल्यांकन.— (1) पूर्व अर्हित परामर्शियों के वित्तीय प्रस्ताव सार्वजनिक रूप में खोले जाएंगे । प्रस्तावित मूल्यों को ऊँचे से पढ़ा जाएगा । विवरणों को बोलियों के खोलने के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा ।

(2) सचिव, वित्तीय प्रस्तावों का पुनर्विलोकन करवाएगा । गणितीय त्रुटियों को शुद्ध किया जाएगा । एकरूप विक्रय (विनियम) दरों का प्रयोग करते हुए एकल करैसी में मूल्य को परिवर्तित किया जाएगा ।

(3) निम्नतम लागत के प्रस्ताव को 100 अंक का वित्तीय स्कोर दिया जाएगा और अन्य प्रस्तावों को उनकी कीमतों के प्रतिलोम अनुपात में वित्तीय स्कोर प्रदान किए गए ।

12. वित्तीय और तकनीकी अंकों का मूल्यांकन.— (1) तकनीकी और वित्तीय प्राप्त अंकों (स्कोर) का तोलन करते हुए और उन्हें जोड़ते हुए कुल अंक प्राप्त किए जाएंगे । वित्तीय अंक के लिए तोलन ऐसे होगा जैसे कि प्रत्येक मामले में सौंपे कार्य की जटिलता और गुणवत्ता के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विहित किया जाएगा । तथापि, किसी भी मामले में माप, वित्तीय स्कोर के लिए 0.3 से अधिक नहीं होगा ।

(2) आयोग, तकनीकी और वित्तीय दोनों के लिए एक वार्ता समिति नियुक्त कर सकता है । जहाँ तकनीकी वार्ता की जानी है वहाँ, परामर्शियों की पूर्व-अर्हता से पहले ही पूरी की जाएगी । वित्तीय वार्ता वित्तीय प्रस्ताव के किन्हीं भी पहलुओं पर, जिनमें स्टॉफ— माह के लिए युनिट दर, आकस्मिकता रकम, यात्रा और निर्वाह व्ययों की प्रतिपूर्ति की एक—मुश्त राशि तथा भुगतान की शर्तें सम्मिलित हैं, की जा सकेगी ।

(3) आयोग, समस्त प्रस्तावों को नामंजूर कर सकेगा यदि वे अप्रत्युत्तरकारी या गैर-अनुकूल पाये जाएं या तो इसलिये कि टी.ओ.आर. का पालन करने में प्रमुख विसंगतियां आ रही हैं या उनमें लागत, मूल प्राक्कलन से अधिक हो रहा है ।

13. एकल स्रोत चयन.— एकल स्रोत उन्हीं आपवादिक मामलों में किया जाएगा जो समुचित हों और जिन में स्पष्ट लाभ दृष्टिगोचर होता हो, क्योंकि :—

(क) कार्य से परामर्शी द्वारा पूर्व में किए गए कार्य करने की प्राकृतिक निरंतरता झलकती हो;

(ख) कोई त्वरित चयन आवश्यक हो;

(ग) सौंपे गए कार्य छोटे हैं और देय फीस प्रत्येक मामले में पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(ङ) केवल एक व्यक्ति अर्हित है या उसे सौंपे गए कार्य का अनुभव है ।

14. वैयक्तिक परामर्शियों का चयन.— (1) वैयक्तिक परामर्शी या रिटेनर परामर्शी ऐसे कार्य के लिये नियोजित किये जायेंगे जिसके लिये कार्मिकों की टीम अपेक्षित नहीं है; जहाँ कोई अतिरिक्त बाहरी (गृह/कार्यालय) वृत्तिक मदद अपेक्षित नहीं है और जहाँ व्यक्ति के अनुभव, विशेषज्ञता, अर्हताएँ और प्रात्यायक सर्वोपरि आवश्यकता हैं ।

(2) कार्य के लिये वैयक्तिक परामर्शी या रिटेनर परामर्शी उनकी अर्हताओं के आधार पर चुने जाएंगे । उनका चयन परिचय या कार्य में रुचि प्रकट कर रहे व्यक्तियों की अर्हताओं की तुलना या आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क साधने पर शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव तथा स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक पद्धति और सरकारी संगठन की जानकारी के आधार पर योग्यता निर्णित की जाएगी ।

15. अन्य शर्तें और निबंधन.— (1) परामर्शियों को किसी ऐसे कार्य के लिये किराये पर नहीं लिया जाएगा जो दूसरे मुवकिल के साथ उनकी पूर्व या वर्तमान आबद्धताओं से टकराते हों या उनको ऐसी स्थिति में रख देते हों जिससे वे कार्य को उद्देश्यक परक और निष्पक्ष रूप से करने में समर्थ न हो सकें ।

(2) परामर्शी आयोग के अध्यक्ष या आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा किन्तु वह स्वतंत्र वृत्तिक विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करने का दायी होगा ।

(3) परामर्शी उसकी/उनकी रिपोर्ट/सलाह, आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

(4) परामर्शी अधिनियम या नियमों या विनियमों के संबंध में आयोग का अधिकारी नहीं होगा किन्तु समेकित पारिश्रमिक और इन विनियमों में दी गई अन्य शर्तों के अतिरिक्त परामर्शी की नियुक्ति की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि आयोग द्वारा विनिश्चित की जाएँ ।

(5) आयोग के विनियमों और आदेशों के अनुपालन की दशा में आयोग अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन उपबंधों के अनुसार यथोचित कार्यवाही करेगा ।

(6) आयोग को किसी परामर्शी को नियुक्त करने या बर्खास्त करने या किसी परामर्शी की सेवा की शर्तों में कटौती करने या विस्तार करने का पूर्ण और अनिर्बाधित अधिकार होगा ।

(7) यहाँ करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व आयोग कार्यक्षेत्र में संशोधन या परिवर्तन करता है, वहाँ आयोग स्वविवेकानुसार और संशोधन/परिवर्तन के स्वरूप को देखते हुए, चाहे तो करार के कार्यक्षेत्र में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है और परामर्शी से आपसी सहमति से अतिरिक्त फीस या उसमें कमी तय कर सकता है या बचनबद्धता को रद्द कर सकता है और फिर से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है ।

(8) यहाँ करार पर हस्ताक्षर करने के बाद में आयोग कार्यक्षेत्र में संशोधन या परिवर्तन करता है, वहाँ आयोग और परामर्शी की आपसी सहमति द्वारा अतिरिक्त फीस या उसमें कमी तय की जाएगी ।

16. आयोग की अंतर्निहित व्यावृत्ति.— आयोग को इन उपबंधों की कोई भी बात किसी ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने से बाधित नहीं करेगी जो इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत है । यदि आयोग मामले या मामले के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से विनियमों में विहित प्रक्रिया से हट सकेगा ।

17. कठिनाई दूर करने की शक्ति.— यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो, तो आयोग को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत न होते हुए कोई भी कार्य कर सकेगा जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन हो ।

18. निरसन और व्यावृत्ति.— (1) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2001 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के हेतु हुए भी .—

(क) निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात या कार्रवाई जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति, या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज या लिखित या जारी किया गया कोई निदेश, जहाँ तक इन विनियमों के उपबन्धों के असंगत नहीं है, इन विनियमों के तत्स्थायी उपबन्धों के अधीन किया गया/जारी किया गया समझा जाएगा ।

(ख) इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व में की गई सभी नियुक्तियाँ तथा निष्पादित किए गए दस्तावेज उस अवधि तक जिसके लिए उक्त नियुक्ति की गई है या दस्तावेज निष्पादित किया गया है, जारी रहेंगे ।

आयोग के आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—

सचिव

हि0 प्र0 विद्युत विनियामक आयोग ।

अनुसूचि-क

..... के एक पक्ष तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (इसके पश्चात् इसका संदर्भ "आयोग") दूसरे पक्ष के बीच माह के दिन ,को हुए करार के अनुच्छेद ।

जबकि आयोग ने प्रथम पक्ष पार्टी को एक परामर्शी के रूप में विनियोजित किया है तथा प्रथम पक्ष पार्टी इसके आगे निहित निबंधन एवं शर्तों पर आयोग को परामर्शी सेवायें देने के लिए सहमत है ।

अब ये साक्षी प्रस्तुत करते हैं तथा दोनों संबन्धित पक्ष निम्नवत रूप से सहमत हैं कि :—

1. प्रथम पक्ष आयोग तथा इसके अधिकारियों एवं प्राधिकारियों, जिनके मातहत आयोग समय-समय पर उन्हें रखेगा, के आदेशों का पालन करेगा ।

2. प्रथम पक्ष अनुबंध "क" में यथानिहित कार्य को से शुरू करके की अवधि में पूरा करेगा ।
3. प्रथम पक्ष को निम्नवत् भुगतान किया जाएगा :—
4. अदायगी कार्यक्रम निम्नवत् होगा:—
5. परामर्शी कार्य के संबंध में स्थानीय यात्रा के लिए प्रथम पक्ष को कोई यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।
6. प्रथम पक्ष आयोग द्वारा अथवा आयोग के निर्देश पर किसी संगठन द्वारा दी गई सूचना तथा ऑकड़ों को किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा । ऐसे सभी दस्तावेज और विनियोजन पर रहने के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उसकी जानकारी में रहने वाली इस प्रकार की अन्य सूचना आयोग की सम्पत्ति होंगे ।
7. प्रथम पक्ष यह वचन देता है कि इस विनियोजन का उसके अन्य ग्राहकों के प्रति पूर्व अथवा वर्तमान दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही उसे इस विनियोजन के जिम्मेदारीपूर्वक तथा निष्पक्ष निर्वहन में परेशानी होगी ।
8. प्रथम पक्ष द्वारा कार्य के किसी भाग को ऊपर दोनों पक्षों में यथा-सम्मत समय-अनुसूचि के भीतर पूरा न किए जाने की अवस्था में दूसरा पक्ष उस कार्य को किसी अन्य अभिकरण से प्रथम पक्ष के जोखिम तथा लागत पर पूरा करवा लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।
9. इस करार के बारे में दोनों पक्षों के बीच कोई मतभेद या विवाद होने पर उसे आयोग द्वारा नामित मध्यस्थ को भेजा जाएगा । यह कार्यवाई समय-समय पर यथा-संशोधित माध्यस्थम और रूलह अधिनियम, 1996 के तहत की जाएगी ।
10. प्रथम पक्ष को शुल्क का भुगतान, उस समय लागू कानून के अनुरूप रत्रोत पर आयकर कटौती के पश्चात् किया जाएगा ।
11. आयोग को बिना कारण बताए परामर्शी के विनियोजन पर प्रतिबंध लगाने, उसे समाप्त अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा । इस प्रकार के मामलों में प्रथम पक्ष को इस प्रकार के प्रतिबंध, समापन अथवा निरस्तीकरण से पूर्व पूरे किए गए कार्य पर विचार करके प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसका निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा तथा

आयोग का निर्णय अंतिम एवं आबद्धकर होगा । इस प्रकार के मामले में निर्धारित तथा प्रदत्त प्रतिपूर्ति, अंतिम अदायगी के रूप में मानी जाएगी ।

12. किसी ऐसे मामले, जिसके लिए उपबन्ध इस करार में नहीं किया गया है, के संबंध में परामर्शियों के विनियोजन के विषय में सरकार के सामान्य अनुदेशों में अन्तर्विष्ट उपबन्ध लागू होंगे ।

प्रथम पक्ष तथा आयोग की ओर से उपर्युक्त के साक्षी के रूप में ऊपर लिखित दिन तथा वर्ष को सहमत हुए ।

..... की उपस्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित ।

..... की उपस्थिति में आयोग के लिए तथा आयोग की ओर से द्वारा हस्ताक्षरित ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2005

No. HPERC/Secy./704/2005-1011.— The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 181, read with sub-section (4) of section 91 of the Electricity Act, 2003 (Act No.36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf are hereby published, as required by sub-section (3) of section 181 of the Electricity Act, 2003, for the information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration, after the expiry of thirty days

from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with the objections/suggestions which may be received in respect thereto within the aforesaid period.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title, commencement and application.— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires;—

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "Chairman" means the Chairperson of the Commission;
- (c) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (d) "Consultant" includes any individual, firm, body or association of persons, not in the employment of the Commission, who or which possesses or has access to any specialised knowledge, experience or skill and who may be appointed as such to assist the Commission on any matter required to be dealt with by the Commission under the Act;
- (e) "Officer" means an officer of the Commission.
- (f) "Secretary" means the Secretary of the Commission and includes any other officer of the Commission authorised in his absence to discharge his duties and perform his functions; and
- (g) other words or expressions occurring in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall bear the same meaning as in the Act.

3. Scope of work.— (1) The Commission may, in its sole discretion, appoint Consultants, required to assist it in discharge of its functions, for any matter, using such procedures as it may deem appropriate, having regard to the nature and complexity of the matter.

(2) Consultants will not be normally appointed for routine day to day work for which staff is available.

(3) Consultants would be engaged for executing specialised tasks for which skills are either not available within the staff of the Commission or where the nature of job is highly technical, specific or time-bound.

(4) Detailed terms of engagement will be drawn up in each case and agreed to between the Consultant and the Commission prior to the award of consultancy.

(5) The terms of engagement would specify the exact nature of the tasks to be undertaken by the Consultant, the time allowed for completion of each task and the specific outputs that are to be provided by the Consultant in relation to each task.

4. Categorisation of Consultants.— (1) Individual Consultants will be categorised into one of three levels of Advisor, Retainer Consultant and Consultants based on their expertise and experience, as per the table given below:—

Category	Minimum Professional qualifications	Minimum Professional experience
(a) <u>Advisers</u>	Ph.D/ Master Degree	15 years with Ph.D or 18 years with Master Degree.
(b) <u>Retainer Consultants</u>	Master Degree/ Bachelor.	15 years with Master Degree or 18 years with Bachelor Degree.
(c) <u>Consultants</u>		
(i) Sr. Consultants	Ph.D/Master Degree	8 years with Ph.D or 12 years with Master Degree.
(ii) Consultants	Ph.D/Master Degree/ Bachelor Degree.	3 years with Ph.D or 5 years with Master Degree/ 8 years Bachelor Degree.
(iii) Junior Consultant	Master or Bachelor Degree.	1 year.

Note.— In the case of Lawyers, Accountants, Engineers and other highly specialised professionals, the minimum educational qualifications will be the relevant professional qualifications.

(2) The Commission may in appropriate case, for reasons to be recorded in writing, relax the minimum educational qualifications or the minimum experience, keeping in view the overall expertise and experience of the person being considered for engagement as Consultant in the specific area.

5. Fees and other charges.—(1) When individuals are appointed as Consultant for a specific purpose, where the experience, expertise, qualifications and credentials are the paramount requirements and the persons of requisite qualification and experience are rarely available, a consolidated monthly payment on man-days basis or man-month basis shall be decided by the Commission depending on the merits of the individual on a case-to-case basis.

(2) For service on daily basis, remuneration per day shall be as follows subject to the condition that engagement on daily rate shall not normally be for more than 7 days at a time.

Category	Remuneration per day (Rs.)	Lump sum per day for daily allowance (when on tour) (Rs.)
(a) Advisor	5,000/-	2,000/-
(b) Retainer Consultant	Consolidated fee per month as may be mutually negotiated between the Commission and the Consultant.	Daily allowance as admissible to Grade-I Officers of the Govt. of Himachal Pradesh.
(c) Consultants:		
(i) Sr. Consultant	3,000/-	1,500/-
(ii) Consultant	2,000/-	1,500/-
(iii) Junior Consultant	1,000/-	1,000/-

(3) In the case of institutional Consultants rates normally will be as determined through competitive bidding. In exceptional cases where single source selection is required due to reasons as explained in regulation 13, the rates of different levels of individual Consultants will be used to determine the reasonableness of the cost allocated to Consultant

time in the proposal. A maximum of 10% over the cost of Consultant time so arrived will be allowable for overheads for office expenses like telephone, photocopying, fax expenses etc. Additional upto a limit of 10% of the cost of Consultant time will be payable as contingencies wherever required, will be payable at rates approved by the Commission.

(4) In the case of the Retainer Consultant monthly-consolidated overhead office expenses like telephone, photocopying, fax expenses etc. and contingencies would be limited to 1/3rd of the monthly-consolidated fees payable.

(5) The Consultants until and unless allowed by the Commission, will work with the Commission at its headquarters. Where the Consultant has to incur expenditure on official travel and stay at a place away from the normal place of duty, the Commission will reimburse D.A by allowing an additional expenditure in lump sum. The number of days on which this lump sum will be payable will be determined as appropriate in each case. The cost of travel will be separately reimbursed by an appropriate Class of travel as decided by the Commission, which will never be lower than that permitted for a Grade-I Gazetted Officer of the Government of Himachal Pradesh.

(6) These regulations regarding fees payable will also apply to former and retired Government officers/servants engaged as Consultants.

6. Appointment of Consultants.— (1) Terms of Reference (TOR) for the appointment of Consultants for specific tasks will be prepared by an officer of the Commission and will be submitted to the Secretary for seeking the approval of the Commission.

(2) The scope of the services described in the TOR shall be compatible with the available budget.

(3) The Commission may decide either to invite combined technical and financial proposals or separate technical and financial proposals.

(4) The Commission will prescribe the minimum qualifying mark for the technical bid.

(5) After approval of the Terms of Reference (TOR) by the Commission, the Secretary will invite proposals from interested Consultants, ensuring that appropriate publicity is given in each case. It will not, however, be necessary to go through the process of issue of public advertisement particularly where the value of the fee is below Rs. 5 lakh in each case, where Commission may call for application or offer or nomination from such individuals, firms, companies, association of persons, bodies, institutions as the Commission may consider appropriate. The decision of the Commission shall be final in this regard.

7. Request for proposals.— The request for proposal shall include the following:—

- (1) A letter of invitation stating the intention of the Commission to enter into a contract for provision of a consulting services, the source of funds, the details of the plan and the date, time and address for submission of proposals.
- (2) Information to Consultants shall contain all necessary information that will help Consultants in preparation of responsive proposals by providing information on the evaluation process and by indicating the evaluation criteria and factors and their respective weights and the minimum pre-qualification score
- (3) Terms of Reference (TOR) shall be prepared to define clearly the objectives, goals and scope of the assignment and provide background information including a list of existing relevant studies and basic data to facilitate the Consultants in preparation of their proposals. If transfer of knowledge, training is an objective, the TOR will detail the number of staff to be trained. TOR shall list the services and surveys necessary to carry out the assignment and the expected outputs (for example reports, data, surveys, evaluation, assessment etc.) linked to each task in the TOR.
- (4) Draft contract shall be as per performa in Schedule-‘A’.

8. Receipt of proposals.— (1) Enough time shall be allowed for the Consultants to prepare and submit their proposals. While the time allowed shall depend on the assignment, it will normally be not less than two weeks, during which period firms may seek clarifications about the information provided in the TOR.

(2) The Commission may decide to extend the deadline for submission of proposals, as may be deemed appropriate by it.

(3) No amendments to the technical or financial proposals shall be accepted after the deadline except before a negotiating committee appointed by the Commission. The proposals shall be submitted in sealed cover. Where the Commission prescribes that separate technical and financial proposals are to be submitted those shall be submitted in separate sealed envelopes.

9. Evaluation of proposals.— Proposals will be evaluated both on the basis of quality as well as cost. Where the Commission decides that proposals are to be evaluated separately on technical and financial basis, the evaluators of the technical proposal shall not have access to the financial proposals, until the technical evaluation is completed.

10. Technical Evaluation.— (1) Technical evaluation will be done by a Committee nominated by the Commission taking into account the following criteria. Each criterion shall be marked on a scale of 1 to 100 and then the marks for each criteria shall be weighted to become average technical scores. Weights in the following ranges will be used by the technical committee with the approval of the Commission to calculate the weighted average technical score for each proposal:—

Criterion	Range of Weights
The Consultant's relevant experience for the assignment.	0.10 to 0.20
The quality of the methodology proposed	0.20 to 0.50
The qualifications of the key staff proposed	0.30 to 0.60
The extent of transfer of knowledge to the staff of the Commission.	0.00 to 0.05

Note.—The mix of weights approved by the Commission must total to 1.

(2) Where the assignment depends critically on the performance of the key staff, the proposal shall be evaluated on the basis of the qualifications of the individuals proposed to be appointed using the following criteria:—

- (a) **General qualifications.**— General education and training, length of experience, positions held, time with the consulting firm as staff, experience in other countries etc.
- (b) **Adequacy for the assignment.**— Education, training, experience in the specific sector, field, subject and relevance to the particular assignment.
- (c) **Regional Experience.**— Knowledge of the administrative system, organisation and culture at the local/regional level.

(3) After the technical evaluation is completed the Commission shall inform those Consultants whose proposals did not meet the minimum qualifying mark or were considered non-responsive to the terms of reference and their financial proposals will be returned unopened after completing the selection process. Simultaneously, those Consultants who have secured the minimum qualifying marks shall be informed about the date and time for opening the financial proposals giving sufficient time for the Consultants to be present at the opening should they so desire.

11. Financial Evaluation.— (1) The financial proposals of the pre-qualified Consultants will be opened publicly. The proposed prices shall be read aloud and recorded in a minute of the public opening.

(2) The Secretary will cause a review of the financial proposals to be done. Arithmetical errors will be corrected. The cost will be converted to a single currency using uniform selling (exchange) rates.

(3) The proposal with lowest cost will be given financial score of 100 and other proposals given financial scores that are inversely proportional to their prices.

12. Evaluation of financial and technical scores.— (1) The total scorer shall be obtained by weighting the technical and financial scores and adding them. The weight for the financial score shall be as prescribed by the Commission in each case taking into account the complexity of the assignment and the relative importance of quality. However, the weight will never exceed 0.3 for the financial score in any case.

(2) The Commission may appoint a negotiating committee to enter into both technical and financial negotiations. Where technical negotiations are conducted those will be completed prior to pre-qualification of the Consultants. Financial negotiations can be entered into for any aspect of the financial proposal including the unit rates for staff months, contingency amount, lump sum reimbursement of travel and living expenses and payment terms.

(3) The Commission may reject all proposals if they are found to be unresponsive or unsuitable either because they represent major deficiencies in complying with the TOR or they involve cost substantively higher than the original estimate.

13. Single source selection.— Single source selection shall be used only in exceptional cases where it is appropriate and represents a clear advantage because.—

- (a) the tasks represent a natural continuation of previous work carried out by the Consultant; or
- (b) a rapid selection is essential; or
- (c) assignments are small and the fee payable does not exceed Rs. 5 lakhs in each case; or

- (d) only one firm or individual is qualified or has experience for the assignment.

14. Selection of individual Consultants.— (1) Individual Consultant or the Retainer Consultant will be employed for assignments for which teams of personnel are not required, no additional outside (home office) professional support is required and where the experience, expertise and qualifications and credentials of the individual are the paramount requirement.

(2) Individual Consultants or the Retainer Consultant will be selected on the basis of their qualifications for the assignment. They may be selected on the basis of references or through comparison of qualifications among those expressing interest in the assignment or approached directly by the Commission. Capability will be judged on the basis of academic background, experience and as appropriate—knowledge of local conditions, administrative system and Government organisation.

15. Other terms and conditions.— (1) Consultants shall not be hired for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients or that may place them in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

(2) The Consultant shall work under the control and supervision of the Chairperson of the Commission or officers as may be authorised by him, but shall be liable to furnish its independent professional expert opinion.

(3) The Consultant shall submit his/their report/advice to the Chairperson.

(4) The Consultant will not be an officer of the Commission in terms of the Act or rules or regulations but other terms of appointment of the Consultant in addition to consolidated remuneration and other conditions given in these regulations, shall be such as may be decided by the Commission.

(5) In case of non-compliance of the regulations and orders of the Commission, the Commission may take suitable action as per the provisions under the Act, rules and regulations or the Commission may take any other action as it may deem as proper.

(6) The Commission shall have full and unrestricted right to appoint a Consultant or terminate, curtail or extend the terms of any Consultant at its sole discretion.

(7) Where the Commission amends or alters the scope of work at any time before the signing the contract, the Commission may, at its discretion and having regard to the nature of such amendment/alteration, either so amend or alter the scope of work in the contract and mutually agree the additional fees or savings therein with the Consultant or cancel the engagement and invite fresh proposals.

(8) Where the Commission amends or alters the scope of work after signing the contract, the additional fees and charges or savings therein shall be mutually agreed between the Commission and the Consultant.

16. Saving of inherent power of the Commission.— Nothing in these provisions shall bar the Commission from adopting a procedure which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure prescribed in these regulations.

17. Power to remove difficulties.— If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

18. Repeal and savings.— (1) The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2001 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal.—

- (a) anything done or any action taken or proposed to have been done or taken including any appointment made, or any document or instrument executed or any direction given under the repealed regulations, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these regulations, be deemed to have been done, taken, made or given under the corresponding provisions of these regulations;

- (b) all appointments made and documents executed before the commencement of these regulations, shall continue to have effect till the expiry of the period for which such appointment has been made or the documents has been executed.

By order of the Commission,

Sd/-
Secretary.

Schedule-'A'

ARTICLES OF AGREEMENT made on this _____ day of _____ BETWEEN _____ of _____ of the one part and the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter called "the Commission") of the other part.

WHEREAS the Commission has engaged the party of the first part as a Consultant and the party of the first part has agreed, to provide the consultancy services to the Commission, on the terms and conditions hereinafter contained.

NOW THESE PRESENTS WITNESS and the parties hereto respectively agree as follows:

The party of the first part shall submit himself to the orders of the Commission and of the officers and authorities under whom he may from time to time be placed by the Commission.

2. The party of the first part shall complete the assignment as contained in Schedule-
'A' within a period of _____ commencing from _____.
3. The party of the first part shall be paid as under:
4. The schedule of payments shall be as under:
5. No TA/DA shall be admissible to the party of the first part for local journeys in connection with the consultancy assignment.
6. The party of the first part shall not disclose to any unauthorised person any information and data that may be supplied to him by the Commission or by any other organisation, under the directions of the Commission. All such documents or any information that may have come to his knowledge directly or indirectly by virtue of the assignment shall be the property of the Commission.
7. The party of the first part undertakes that this assignment shall not be in conflict with his prior or current obligation to other clients nor shall it place him in a position of not being able to carry out the assignment objectively and impartially.

8. In case of any default on the part of the party of the first part in completion of the work within the time schedule agreed to between the parties as herein above, the party of the second part shall be at liberty to get the work completed from any other agency at the risk and cost of the party of the first part.
9. In case of any differences or disputes between the parties arising out of this Agreement, it shall be referred for arbitration of a person nominated by the Commission. The proceedings shall be subject to the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended from time to time.
10. The payment of fee to the party of first part shall be made by the Commission after the deduction of tax at source in accordance with law for the time being in force.
11. The Commission reserves its rights to foreclose, terminate or cancel the engagement of the Consultant without assigning any reasons. In such cases party of the first part shall be paid remuneration after taking into consideration the part of work completed prior to such foreclose, termination or cancellation of the engagement as may be decided by the Commission, and the decision of the Commission shall be conclusively and binding. The remuneration so fixed and paid shall be deemed to be the final payment in such cases.
12. In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the provisions contained in the general instructions of the Government on the subject engagement of consultants shall apply.

In witness whereof the party of the first part and _____ to the Commission on behalf of the Commission have hereto put their hands the day and the year first above written.

Signed by _____ the party of the first part in the presence of _____.

Signed by _____ the said of the Commission for and on behalf of the Commission the presence of _____.